[Shri S. Viduthalai Virumbi]

(iv) Grant of bad-climate allowance, winter allowance and project allowance wherever admissible to Departmental employees (in a proportionate manner).

(v) Modification of the only penalty of dismissal and introdouction of less severe penalties also such as censure, etc.

(vi) Change of nomenclature "Extra-Departmental" as "Auxiliary Postal Service".

But surprisingly recommendations of the Savoor Committee have been thrown into the dustbin of the Department. Under these circumstances, Labour unions served a notice of strike in May, 1987 but a settlement holding out promise was reached within a week i.e., on 11-7-1987 and the strike call was withdrawn. However, the principle of pro-rata wages has been rejected.

I, therefore, request the present Government to invite the labour union leaders of all shades including the Labour Progressive Federation, labour wing of the DMK to discuss and decide to absorb EDA employees as group D' and group 'E' of the Postal Department as applicable and to find out a solution to other important issues such as promotion, payment of pro-rata wages, provident fund, family pension, leave with pay, gratuity, group insurance scheme and other related issues of the EDAs.

I hope the present Government will solve the problem of EDAs once and for all and relieve them from the bonded labour system. With these words, I conclude.

Demand for allocating more funds for Nadiad-Bhodasa Rail Project

श्री मीर्जा इर्शादबेग (गुजरात) : उपसभापति महोदया, मेरा यह सौभाग्य था कि आज से 7 वर्ष पूर्व जब मैं इस सदन में पहली बार आया था तो पहले ही दिवस में शायद पहले ही घंटे में जो मैंने अपना एक सप्लीमेंटरी क्वेश्चन किया था वह नादियाड-भोडासा रेल लाइन पर था। सात वर्ष के पश्चात् भी जब मैं रिटायर हो रहा हूं, यह मेरी आखरी स्पीच भी हो सकती है उसमें भी आज मैं वही शब्द बोलने जा रहा हूं, यह मेरी इच्छा है कि यह रेल परियोजना पूरी हो और मेरा सौभाग्य भी है कि रेल मंत्री जी यहां पर उपस्थित हैं।

उप-सभापति : आपकी आखिरी ख्वाहिश रूर पूरी करेंगे।

श्री मीर्जा इर्शादबेग : रेल बजट में नहीं हुई है इसलिए यह आश्वासन में जरूर चाह सकता हूं कि रेल मंत्री जी आने वाले वर्षों में यदि वह रेल मंत्री रहें तो इस परियोजना को सम्पूर्ण करेंगे। (**व्यवधान**)

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडीज) : रेल बजट में इसका प्रावधान है।

श्री मीर्जा इर्शादबेग : उपसभापति महोदया, 1988-89 में रेल का जो एनुअल प्लान था वह 450 करोड़ रुपये था। जिसमें न्यू लाइन्स के लिए प्लानिंग कमीशन ने 195 करोड़ रुपये और गेज कंवर्जन के लिए 60 करोड़ रुपया दिया था। जहां तक तमाम गेज कंवर्जन और नई लाइनों का संबंध है और जो एक्विजिशन और पेंडिंग वाले हैं उनके लिए कम से कम 24 सौ करोड़ रुपयों से भी ज्यादा की आवश्यकता है। अगर प्लानिंग कमीशन ने इसकी अनुमति नहीं दी है तो यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। गेज कंवर्जन और नई लाइनों का ऐसा मामला है जो आने वाले 30 से 50 साल तक भी नहीं निपटाया जा सकता है। जहां तक नाडियाड-कपड़गंज लाइन के कंवर्जन का संबंध है, यह 44.64 किलोमीटर है और इसकी कास्ट 15 करोड़ से भी ज्यादा हो गई है और आज तक इस पर सिर्फ 82 लाख रुपयों का कार्य हुआ है। भोडासा मेरा नेटिव प्लेस है जहां की धरती में बड़ा हुआ हूं और पढ़ा हूं। इसका जो लिंक है, कपड़गंज और भोडासा जो मेरा शहर है, इस शहर को अभी तक पटरी का मुंह देखना भी नसीब नहीं हुआ है। कपडगंज-भोडासा जो नई ब्राडगेज लाइन है, जो 60.50 किलोमीटर; इसकी एक्सपेक्टड

कास्ट 30 करोड़ हो गई है जब कि इस पर सिर्फ 2 करोड़ 56 लाख रुपये भी खर्च नहीं हो पाये हैं । नाडियाड-कपड़गंज गेज कंवर्जन में लैण्ड एक्वीजीशन मे 5 प्रतिशत और अर्थ वर्क में 36 प्रतिशत और माइनर ब्रिजज में 29 प्रतिशत और मेजर ब्रिजज में 33 प्रतिशत की कार्य की प्रगति हुई है । इसी तरह से कपड़गंज-भोडासा में नई लाइन में जो आज तक प्रगति हुई है वह लेण्ड एक्वीजीशन में 98 प्रतिशत की, अर्थ वर्क में 74 प्रतिशत और माइनर ब्रिजेज में 5 प्रतिशत और मेजर ब्रिजज मे 78 प्रतिशत ही इजाफा हुआ है । इस पर हमरी जो पिछली सरकार थी उसने हमारे निरन्तर प्रयासों से काम किया था । मैं पिछली सरकार को बधाई देता हूं, पिछले रेल मंत्री जी को भी बधाई देता हूं, उन्होंने इस दिशा में काम किया था । इसमें मेरे व्यक्तिगत प्रयासों के कारण भी पिछले रेल मंत्री जी ने इस कार्य को पूर्ण करने के लिए पिछले साल के बजट में तीन करोड़ रुपया दिया था । इस कार्य को बहुत तेजी से बढ़ाने और सम्पन्न करने की जरूरत है । मैं सिर्फ एक बात की रफ आपके माध्यम से रेल मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । जब रेल मंत्री जी ने अपना बजट पेश करना था, मैंने उनको एक कागज भी लिख कर दिया था और उनसे मिलकर भी इस बात से उनको अवगत कराया था । जब चुनाव चल रहा था तो गुजरात में चुनावी ढिंढोरे मे इन्होंने यह कहा था कि नाडियाड-कपड़गंज-भोडासा रेलवे लाइन को त्वरित गति से करना हो तो गुजरात की जनता को चाहिए कि वह मत जनता दल के प्रत्याशियों को दे । खेद के साथ कहना पड़ता है कि चुनावी ढिंढोरों मे जनता दल के लोगों ने जो बात कही थी, रेल मंत्री जी ने नाडियाड-कपड़गंज-भोंडासा रेलवे लाइन के लिए अपने बजट में एक पैसा भी नहीं दिया है । मुझे अत्यन्त खेद है कि लोगों को चुनावी ढिंढोरों में जो वचन दिया था, जब उनकी सरकार वहां पर प्रस्थापित हो गई है तो इस सरकार ने इस परियोजना के लिए एक नये पैसे का भी प्रावधान नहीं किया है । रेल मंत्री श्री फर्नांडीज यहां पर बैठे हुए हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि भोडासा एक पिछड़ा हुआ इलाका है, आदिवासी इलाका है, उसका विकास पिछले 40-42 सालों से आजादी के बाद भी नहीं हुआ है और उस इलाके के लोगों को रेल का मुंह देखने को भी नहीं मिलता है । जब वर्तमान वित्त मंत्री श्री मधु दंडवते जी रेल मंत्री थे तो उन्होंने इस परियोजना की गम्भीरता को समझा था और इससे पूर्व हमारी जो कांग्रेस की सरकार थी उसने इसको सिद्धान्ततः स्वीकार किया था । अब जनता दल की सरकार आई है, उसने भी इसको मान्यता दी है क्योंकि उसने चुनाव ढिंढोरों मे लोगों को वचन दिया था, तो मै यह जानकारी लेना चाहता हूं कि अब क्या कारण है कि इस परियोजना को अंधेरे मे धकेल दिया गया है । पिछली सहकार का प्रयास था और उसके प्लानिंग मिनिस्टर ने कहा भी था कि इस योजना को आठवीं योजना के अन्तर्गत सम्पन्न कर लेंगे । लेकिन इस सरकार के आते ही मुझे दिशा बड़ी धुंधली लग रही है । मैं आशा करता हूं और रेल मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि यह बड़ा बैकवर्ड इलाका है, इसके विकास और इस इलाके के लोगों के विकास पर गम्भीरता से विचार किया जाय और मैं इस सरकार से मांग करता हूं कि वह पुनः इस पर विचार करेगी और इसके लिए ज्यादा धनराशि आवंटित करेगी और इस रेलवे की परियोजना को तत्परता से पूर्ण करने की कोशिश करेगी ।

SHRI JAGESH DESAI (Maharashtra): Madam Deputy Chairman, I associate myself with Mr. Mirza Irshadbaig. For so many years it has been like that. (*Interruptions*). I am sure that the Railway Minister will look into this. (*Interruptions*).

THE DEPUTY CHAIRMAN: Generally you don't react. You may reply if you want.

श्री छोटूभाई सुखाभाई पटेल (गुजरात) : मीर्जा इशादबेग जी के प्रिवेलेज का मैं समर्थन करता हूं । और मैं कहना चाहता हूं कि कपड़गंज भोडासा रेल परियोजना जल्दी से कार्यान्वित कराया जाए ।

श्री जार्ज फर्नांडीज : मैं रिप्लाई नहीं दे रहा हूं । यह कहा गया है कि चुनाव के समय कुछ वायदे किये गये थे और जनता को धोखा दिया गया । माननीय सदस्य ने वास्तविक जानकारी न रखते हुए यह आरोप यहां पर लगाया है । इस वर्ष बजट मे इस रेल लाइन पर 6 करोड़ रुपये का प्रावधान हमने किया है । माननीय सदस्य को शायद इसकी जानकारी बिल्कुल ही नहीं है ।

श्री मीर्जा इर्शादबेग : 3 करोड़ पिछली मर्तबा रखा था ।

उपसभापति : अब 6 करोड़ रखा है।

श्री मीर्जा इर्शादबेग : मुझे तो कहीं मिला नहीं ।

Government's move to close novadaya Schools

श्री सुरेन्द्र सिंह ठाकुर (मध्य प्रदेश) : आदरणीय उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान उन नवोदय विद्यालयों की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं जिनको कांग्रेस पार्टी की नीतियों के तहत कांग्रेस पार्टी के नेता, पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय राजीव गांधी जी ने इन उद्देश्यों के साथ स्थापित किया था ताकि ये स्कूल ग्रामीण, जन-जाति और पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले प्रतिभाशाली छात्रों के लिये, भले ही वे गरीब हों ऐसा मौका देंगे जिसके माध्यम से उनकी चहुंमुखी प्रगति हो । इसी के साथ इन स्कूलों का उद्देश्य था कि छोटी छोटी जो धारणायें होती हैं, मानसिकतायें होती हैं, उनसे ऊपर उठकर यह बच्चे नये भारत के अच्छे नागरिक बन सकें । लेकिन कुछ लोगों ने उस समय कहा कि ये स्कूल एक विशेष वर्ग को तैयार करने के लिये खड़े किये गये हैं । यह तर्क भ्रांतिपूर्ण था और इसका उस समय खण्डन किया गया था और इसको हम लोगों ने स्वीकारा था । क्योंकि ग्रामीण जनों, ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को उन बच्चों को जो प्रतिभाशाली हैं मौका देने के लिये इनकी स्थापना की गई थी । इसीलिये उसमे 75 प्रतिशत विद्यार्थी ग्रामीण क्षेत्रों के होते हैं । यह स्कूल, देश में सभी को समानरूप से अवसर मिले, उस दिशा में एक मील का पत्थर सिद्ध होंगे यह आशा उस वक्त व्यक्त की गई थी । आज करीब 261 स्कूल खोले जा चुके हैं । इनमें 18 प्रतिशत हरिजन और 12 प्रतिशत आदिवासी छात्र एडमीशन पाते हैं । इन स्कूलों मे करीब 50 हजार विद्यार्थियों का दाखिला किया जा चुका है । सौ स्कूल प्रतिवर्ष खोलने की योजना थी । लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि शायद, मुझे जो जानकारी है उसके अनुसार वी० पी० सिंह जी की सरकार में, जो खुद शिक्षा मंत्री भी हैं, इस पर पुनर्विचार की बात चल रही है । इस सरकार ने अपने चुनाव घोषणा पत्र और राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कहा है कि हम शहरों और गांवों के अंतर को कम करेंगे । इस अंतर को कम करने वाली सरकार जब ग्रामीण क्षेत्रों मे ऐसे स्कूलों को बंद करने की बात करती है जिन स्कूलों के माध्यम से उन बच्चों को, जो शहरी बच्चों के मुकाबले मे काफी पिछड़े हुए होते हैं उनको उनके समकक्ष लाने की कोशिश की गई है, तो जब यह सरकार उन स्कूलों को बन्द करने की बात करती है तो हमे दुख होता है । अगर इनको बन्द करना है तो देश के सारे पब्लिक स्कूलों को बंद करें । ये पब्लिक स्कूल आज देश को कहां ले जा रहे हैं ? कोई भी व्यक्ति जो गांव से निकल कर आता है, चाहे वह किसी भी फील्ड मे आया हो अपने बच्चों को अंग्रेजी मे शिक्षा दिलवाना चाहता है । यह मानसिकता आज बनती जा रही है । अंग्रेजी की दासता से मुक्त करने के लिये यह कदम नवोदय विद्यालयों के माध्यम से कांग्रेस ने उठाया था । इनको बंद करके यह सरकार पीछे हट रही है और कौन पीछे हट रहा है, वी० पी० सिंह जिन्होंने 22 जनवरी 1990 को साक्षरता दिवस के शुभारम्भ पर पता नहीं किस मूड मे यह कविता कही थी जिसको मैं यहां पर उद्धृत करना चाहता हूं । वे कहते हैं :

मूक, कान्तिहीन, निरीह इन चेहरों पर,
हमें आत्मा की भाषा मुखरित करनी है,